Tribune, Delhi, 11/09/2025
Page No: 10, Size: 14.66cm × 12.83cm

File report on 'proxy rule' by men in local bodies: NHRC

SNEHA RICHHARIYA
TRIBUNE NEWS SERVICE

NEW DELHI, SEPTEMBER 10

The National Human Rights Commission (NHRC) has ordered all states and UTs to submit detailed reports on the practice of "Sarpanch Patis" — wherein male relatives allegedly exercise authority in place of the elected women representatives in Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies.

The NHRC has directed principal secretaries of the Departments of Urban Local Bodies and Panchayati Raj to provide information on the prevalence of such practices and their legality under state laws.

The order follows a complaint highlighting violations of constitutional mandates stemming from proxy governance by male relatives of women sarpanches; and appointment of male relatives as liaison persons by MPs and MLAs.

Rastriya Sahara, Gorakhpur, 11/09/2025
Page No: 2, Size: 11.46cm × 13.49cm

रामस्वरूप विवि में छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में NHRC ने सरकार से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

लखनऊ (एसएनबी)। बाराबंकी स्थित श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में कथित फर्जी एलएलबी दाखिलों के विरोध में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना है और यूपी के मुख्य सचिव व डीजीपी से 15 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

फर्जी एलएलबी दाखिले व छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध पर कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार आयोग ने जताई गंभीर चिंता

शिकायतकर्ता ने एनएचआरसी को बताया कि विश्वविद्यालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए अवैध दाखिले किए। जब छात्रों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस कार्रवाई में कई छात्र घायल हो गए। शिकायत में कहा गया कि यह कदम छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन है। शिकायतकर्ता ने आयोग से मामले में उच्च स्तरीय जांच, जिम्मेदार विश्वविद्यालय और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, तथा घायलों को मुआवजा दिलाने की मांग की है।

एनएचआरसी की कड़ी टिप्पणी:

आयोग ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के दायरे में आते है। मामले की सुनवाई सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। आयोग ने इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान में लिया और यूपी सरकार को निर्देश दिया कि जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए। आयोग ने कहा कि रिपोर्ट की एक प्रति ईमेल के माध्यम से भी भेजी जाए ताकि जल्द से जल्द इस मामले पर आगे की कार्रवाई की जा सके। फिलहाल आयोग राज्य सरकार और पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है।

Rastriya Sahara, Kanpur, 11/09/2025
Page No: 8, Size: 23.28cm × 14.87cm

रामस्वरूप विवि में छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में NHRC ने सरकार से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

फर्जी एलएलबी दाखिले व छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध पर कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार आयोग ने जताई गंभीर चिंता

लखनऊ (एसएनबी)। बाराबंकी स्थित श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में कथित फर्जी एलएलबी दाखिलों के विरोध में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना है और यूपी के मुख्य सचिव व डीजीपी से 15 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

शिकायतकर्ता ने एनएचआरसी को बताया कि वि विद्यालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए अवैध दाखिले किए। जब छात्रों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस कार्रवाई में कई छात्र घायल हो गए। शिकायत में कहा गया कि यह कदम छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन है। शिकायतकर्ता ने आयोग से मामले में उच्च स्तरीय जांच, जिम्मेदार वि विद्यालय और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, तथा घायलों को मुआवजा दिलाने की मांग की है।

एनएचआरसी की कड़ी टिप्पणी: आयोग ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के दायरे में आते है। मामले की सुनवाई सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। आयोग ने इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान में लिया और यूपी सरकार को निर्देश दिया कि जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए।

आयोग ने कहा कि रिपोर्ट की एक प्रति ईमेल के माध्यम से भी भेजी जाए ताकि जल्द से जल्द इस मामले पर आगे की कार्रवाई की जा सके। फिलहाल आयोग राज्य सरकार और पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है।

बुलडोजर कार्रवाई व आरोपियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक

25 तक डीएम करेंगे मामले का निस्तारण

लखनऊ (एसएनबी)। बाराबंकी के देवाचिनहट रोड स्थित श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर अवैध कब्जे के आरोप में की जा रही बुलडोजर कार्रवाई और जमीन की नापजोख पर फिलहाल हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने रोक लगा दी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है कि मामले की जांच और इसका निस्तारण अब 25 सितंबर तक बाराबंकी के डीएम करेंगे। याची की ओर से जमीन मामले में हुई करवाई को चुनौती दी है।

यूनिवर्सिटी प्रशासन की एक अन्य याचिका पर हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के आरोपी लोगों की संभावित गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को पुलिस विवेचना में सहयोग करना होगा। सुनवाई के दौरान कहा गया कि बीते एक सितंबर को बिना मान्यता एलएलबी-बीबीए की पढ़ाई कराए जाने के आरोपों को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर प्रदर्शन किया था। हंगामे के दौरान छात्रों पर हमले की स्थिति बनी और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें 24 कार्यकर्ता घायल हो गए। बाद में तीन सितंबर को उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ केस दर्ज कराया। इससे पहले सदर तहसीलदार न्यायालय ने 25 अगस्त को यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में करीब 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। छह सितंबर की सुबह एडीएम, एएसपी, एसडीएम, सीओ ने भारी पुलिस बल व पीएसी के साथ पहुंचकर यूनिवर्सिटी परिसर की नापजोख कराई और शाम को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में फार्मेसी विभाग का एनिमल हाउस व गार्ड रूम बुलडोजर से गिरवा दिया। सात सितंबर को भी जमीन की पैमाइश का काम जारी रहा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताते हुए दो अलग - अलग याचिकाएं दाखिल कर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

यूनिवर्सिटी की ओर से पेश अधिवक्ता अमित जायसवाल ने बताया कि कोर्ट ने फिलहाल कब्जे से जड़ी कार्रवाई पर रोक लगाई है और जांच का जिम्मा डीएम को सौंपा है। साथ ही मामले में आरोपियों की संभावित गिरफ्तारी पर भी अंतरिम रोक लगा दी गई है। अब 25 सितंबर तक कोर्ट के आदेश के तहत डीएम इस पूरे मामले की सुनवाई और जांच करेंगे। इससे फिलहाल यूनिवर्सिटी प्रशासन को राहत मिली है।

Rastriya Sahara, Lucknow, 11/09/2025
Page No: 11, Size: 49.00cm × 21.56cm

रामस्वरूप विवि में छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में NHRC ने सरकार से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

लखनऊ (एसएनबी)। बाराबंकी स्थित श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में कथित फर्जी एलएलबी दाखिलों के विरोध में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना है और यूपी के मुख्य सचिव व डीजीपी से 15 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

फर्जी एलएलबी दाखिले व छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध पर कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार आयोग ने जताई गंभीर चिंता

शिकायतकर्ता ने एनएचआरसी को बताया कि विश्वविद्यालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए अवैध दाखिले किए। जब छात्रों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस कार्रवाई में कई छात्र घायल हो गए। शिकायत में कहा गया कि यह कदम छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन है।

शिकायतकर्ता ने आयोग से मामले में उच्च स्तरीय जांच, जिम्मेदार विश्वविद्यालय और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, तथा घायलों को मुआवजा दिलाने की मांग की है।

एनएचआरसी की कड़ी टिप्पणी: आयोग ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के दायरे में आते हैं। मामले की सुनवाई सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। आयोग ने इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान में लिया और यूपी सरकार को निर्देश दिया कि जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए। आयोग ने कहा कि रिपोर्ट की एक प्रति ईमेल के माध्यम से भी भेजी जाए ताकि जल्द से जल्द इस मामले पर आगे की कार्रवाई की जा सके। फिलहाल आयोग राज्य सरकार और पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है।

बुलडोजर कार्रवाई व आरोपियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक

लखनऊ (एसएनबी)। बाराबंकी के देवा-चिनहट रोड स्थित श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर अवैध कब्जे के आरोप में की जा रही बुलडोजर कार्रवाई और जमीन की नापजोख पर फिलहाल हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने रोक लगा दी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है कि मामले की जांच और इसका निस्तारण अब 25 सितंबर तक बाराबंकी के डीएम करेंगे। याची की ओर से जमीन मामले में हुई करवाई को चुनौती दी है।

25 तक डीएम करेंगे मामले का निस्तारण

यूनिवर्सिटी प्रशासन की एक अन्य याचिका पर हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के आरोपी लोगों की संभावित गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को पुलिस विवेचना में सहयोग करना होगा। सुनवाई के दौरान कहा गया कि बीते एक सितंबर को बिना मान्यता एलएलबी-बीबीए की पढ़ाई कराए जाने के आरोपों को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर प्रदर्शन किया था। हंगामे के दौरान छात्रों पर हमले की स्थिति बनी और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें 24 कार्यकर्ता घायल हो गए। बाद में तीन सितंबर को उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ केस दर्ज कराया। इससे पहले सदर तहसीलदार न्यायालय ने 25 अगस्त को यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में करीब 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। छह सितंबर की सुबह एडीएम, एएसपी, एसडीएम, सीओ ने भारी पुलिस बल व पीएसी के साथ पहुंचकर यूनिवर्सिटी परिसर की नापजोख कराई और शाम को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में फार्मेसी विभाग का एनिमल हाउस व गाई रूम बुलडोजर से गिरवा दिया। सात सितंबर को भी जमीन की पैमाइश का काम जारी रहा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताते हुए दो अलग - अलग याचिकाएं दाखिल कर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यूनिवर्सिटी की ओर से पेश अधिवक्ता अमित जायसवाल ने बताया कि कोर्ट ने फिलहाल कब्जे से जुड़ी कार्रवाई पर रोक लगाई है और जांच का जिम्मा डीएम को सौंपा है। साथ ही मामले में आरोपियों की संभावित गिरफ्तारी पर भी अंतरिम रोक लगा दी गई है। अब 25 सितंबर तक कोर्ट के आदेश के तहत डीएम इस पूरे मामले की सुनवाई और जांच करेंगे। इससे फिलहाल यूनिवर्सिटी प्रशासन को राहत मिली है।

Tribune

Report on `sarpanch pati' proxy practice in local bodies, NHRC directs states

https://www.tribuneindia.com/news/localgovernance/report-on-sarpanch-pati-proxy-practice-in-local-bodies-nhrc-directs-states

Sneha Richhariya | Tribune News Service

New Delhi, Updated At : 03:33 AM Sep 11, 2025 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has ordered all states and UTs to submit detailed reports on the practice of "\ISarpanch Patis\I" — wherein male relatives allegedly exercise authority in place of the elected women representatives in Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs).

The commission has directed principal secretaries of the Departments of Urban Local Bodies and Panchayati Raj to provide information on the prevalence of such practices and their legality under state laws.

The order follows a complaint highlighting violations of constitutional mandates and human rights stemming from proxy governance by male relatives of women sarpanches.

The NHRC pointed to the Supreme Court's recent condemnation of the '\ISarpanch Pati\I' phenomenon, describing it as unconstitutional and unlawful. "It has been alleged that, notwithstanding constitutional and judicial safeguards intended to empower women, elected women representatives are often reduced to nominal or symbolic heads, while actual administrative and decision-making powers are exercised by their male relatives," said the panel.

The complaint also flagged the appointment of male relatives as liaison persons by MPs and MLAs, resulting in undue interference with local self-governance bodies. Such practices, it warned, undermine democratic values and the principles of devolution enshrined in the Constitution.

The NHRC cited the 73rd Constitutional Amendment, which mandates at least one-third reservation for women in panchayat chairperson positions, stating that proxy governance "defeats the constitutional mandate" and compromises accountability to the electorate.

While the Ministry of Panchayati Raj has issued advisories and proposed penalties against "\ISarpanch Pati\I" practices, the NHRC emphasised the need to focus on Urban Local Bodies as well.

Presided over by member Priyank Kanoongo, the NHRC Bench invoked Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, directing states to submit action-taken reports within four weeks.

The commission directed the states and UTs to "furnish a detailed action taken report (ATR) to it within 4 weeks in respect to the above, including the number of

complaints/cases identified, measures taken to curb practice of proxy representation, directives issued to subordinate officers and field-level functionaries and any other relevant action taken to ensure compliance with the constitutional mandate."

The commission also urged the authorities to treat the matter with utmost seriousness and ensure prompt and effective action. In February this year, a Ministry of Panchayati Raj panel recommended “exemplary penalties” for proven cases of proxy leadership to curb the practice of ‘Pradhan Pati’, ‘Sarpanch Pati’ or ‘Mukhiya Pati’ in gram panchayats.

“Exemplary penalties should be enforced for proven cases of proxy leadership, deterring male relatives’ interference,” the committee headed by former Mines Secretary Sushil Kumar said in its report "Transforming Women’s Representation and Roles in Panchayati Raj Systems and Institutions: Eliminating Efforts for Proxy Participation."

India has about 2.63 lakh panchayats. Among the 32.29 lakh elected representatives in these local governance bodies, women account for 46.6 per cent. While women’s representation has increased, their real participation in ground-level decision-making remains low.

The Daily Jagran

Jharkhand: Man, Arrested For Strangulating Lover, Her Friend To Death, Dies By Suicide In Police Custody

Shrikant Chaudhary from Kharsan village, Jharkhand, died by suicide after being arrested for allegedly strangling two women, Soni Devi and Rinku Devi, in a “revenge over a love affair” case. Investigation revealed a two-year illicit relationship, prior threats, and recovered bodies. The incident sparked widespread protests and local outrage.

https://www.thedailyjagran.com/india/jharkhand-man-arrested-for-strangulating-lover-her-friend-to-death-dies-by-suicide-in-police-custody-10266089

By Yashashvi Tak

Wed, 10 Sep 2025 12:44 PM (IST)

A man, Shrikant Chaudhary, from Kharsan village in Jharkhand's Giridih district, died by suicide on Tuesday in a case described as “revenge over a love affair” after being arrested for allegedly murdering two women, Soni Devi (23) and Rinku Devi (31), both residents of Neemadhi village. Preliminary police investigations suggest the women were strangled to death, and their bodies have been sent for post-mortem examination.

Shrikant Chaudhary And Soni Devi In Relationship

According to police, Chaudhary had been in a relationship with Soni Devi for the past two years, despite her being married. Soni, in her third marriage, had a husband lodged in jail for a murder case. Chaudhary, who worked in Mumbai’s film industry, reportedly suspected Soni of having relationships with other men. He returned to the village and allegedly killed her in the forest by strangulation as an act of revenge. To eliminate evidence, he also killed her friend, Rinku Devi, a woman with seven children.

Panchayat Declared The Affair Illegal

Earlier, a panchayat had declared the affair “illegal” and fined Chaudhary Rs 1.7 lakh, but the relationship continued. According to an IANS report, Soni’s family alleged that Chaudhary had recently threatened her, saying he would kill her if she stopped communicating with him. Last Thursday, Soni went to the forest to collect leaves with Rinku, after which both went missing.

Two days later, Soni’s mother filed a missing persons complaint at the Gawan police station, suspecting Shrikant Chaudhary’s involvement. She also handed over her daughter’s mobile phone to assist the investigation.

Analysis of call detail records led investigators to Chaudhary, who, during interrogation, confessed to the murders. Acting on his disclosure, police recovered the bodies from Golgo Hill forest, about four kilometres from Neemadhi village.

Villagers Protest Outside Police Station

The incident sparked widespread anger in the area. On Tuesday, hundreds of villagers, along with the victims' families, protested outside Gawan police station, accusing the authorities of negligence and alleging that police had demanded bribes to search for the bodies. The crowd also demanded that the accused be handed over to them.

Sub Divisional Police Officer Rajendra Prasad said that after Choudhary was brought back to the local police station, a crowd gathered outside. "Villagers, especially women, gathered outside the police station demanding that the accused be handed over to them. They said he had killed two women and should be killed in the same way. They threatened that if handed over, they would kill him and go to jail themselves. The situation became tense, but we managed to pacify the crowd," Prasad said.

Prasad denied that there was any custodial violence against Choudhary and said the National Human Rights Commission may conduct an inquiry.

Shrikant Chaudhary Attempted Suicide After Arrest

The SDPO said that he then left the police station to attend a press conference. "By the time I returned, I was informed that the accused had hanged himself in the lockup with a cable wire and a flag rope. When discovered, he was still alive and was rushed first to a local health centre and later to Sadar Hospital, about 70 km away. He died there during treatment," Prasad said.

"Choudhary's death was completely unexpected. We could not imagine he would take such a decision. He had listened to villagers saying that even if he came out alive, they would kill him," Prasad said.

New Laundary

A look at 27 custodial deaths in Tamil Nadu: Most victims were poor and marginalised

An analysis of the custodial deaths in Tamil Nadu in the past four years shows that the majority of victims belonged to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and were from poor economic backgrounds. Many were arrested for petty crimes.

https://www.newslaundry.com/2025/09/10/a-look-at-27-custodial-deaths-in-tamil-nadu-most-victims-were-poor-and-marginalised

By: Abhishek Vijayan & Nithesh Kumar M | 10 Sep, 2025

Support Independent Media

The media must be free and fair, uninfluenced by corporate or state interests. That's why you, the public, need to pay to keep news free.

For P Marimuthu, July 30, 2025 was supposed to mark the end of a long episode of harassment by the Tamil Nadu Forest Department. A day ago, the 48-year-old tribal man had been acquitted by an Udumalpet court in a ganja case—one that activists say he was falsely accused in. The continuous harassment he had faced in connection with the case had made him shift residence to Suryanelli in Kerala from his home at the Mel Kurumalai settlement in Tiruppur, Tamil Nadu.

After finishing the paperwork related to his acquittal, Marimuthu was on the bus back to Suryanelli when he was apprehended again at the state border for allegedly possessing leopard teeth. He was taken into custody by the Kerala Excise Department and later handed over to the Tamil Nadu Forest Department. Activists allege that he was illegally detained at the Udumalpet Forest Range Office that night.

Around 4.30 am on July 31, Marimuthu was found dead in the bathroom of the range office. While the official version is that he took his own life, injuries on his body indicated brutal custodial torture. His family said that Marimuthu had injuries on his hands, head, and neck. This was not the only case, where the Forest Department came under scrutiny for custodial deaths. In April 2025, Senthil, arrested for elephant poaching by the Pennagaram range forest department was found dead in the Pennagaram reserve forest, a fortnight after his alleged escape from custody.

But it is Tamil Nadu police who have the most blood on its hands when it comes to custodial deaths. Marimuthu's death came exactly a month after Ajith Kumar, a security guard at the Badrakaliamman Temple in Sivaganga district, died in police custody on June 28. Ajith Kumar, who was detained for questioning in connection with a theft case, had been brutally assaulted in custody.

These deaths are not isolated incidents—data compiled by human rights organisation People's Watch shows that law enforcers in the state faced allegations of torture after 32

people died in custody during the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) regime between May 2021 and August 2025.

While two of these deaths have been blamed on the Forest Department, the Prohibition Enforcement wing under the Excise Department and Juvenile Justice Department have been accused of causing the death of two other suspects. All the rest died, allegedly, due to police excesses. Significantly, 40% of the victims were from the Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) communities

TNM looked at 27 of these deaths and our analysis of the data for the past four years shows that nine people were declared brought dead to the hospital from police stations, while seven were brought dead from prisons after they were remanded to judicial custody.

One person died immediately after release from custody while two suspects allegedly died by suicide inside police stations. Three people – two from judicial custody and one from a police station – died after being taken to hospitals. Further, there are three cases of people who died allegedly by suicide after being released by the police but these have not been considered for this report.

In most of the cases, the police cited illness as the cause of death. But post-mortem examinations, FIRs, and statements by victims' families say otherwise. Some cases led to suspensions or arrests of police personnel. Others remain under investigation, or have vanished from headlines.

The deaths span the South, North, West, and Central police zones in Tamil Nadu. But it is the South Zone that recorded the highest number of custodial deaths. Comprising Madurai, Tirunelveli, Ramanathapuram, Tenkasi, Virudhunagar, and Sivaganga, the zone accounts for eight of the total custodial deaths in the state. Chennai had the highest count with three cases while Tirunelveli, Virudhunagar, Namakkal, and Thoothukkudi had two cases each.

Custodial deaths aren't, unfortunately, a novelty in Tamil Nadu. Under the rule of All India Anna Dravida Munnetra Kazgagam (AIADMK), between 2016 and 2021, the state saw investigation in 40 custodial death cases in police stations, according data tabled in the Parliament. No police officers faced prosecution during the period though disciplinary action was taken against one officer in 2021-22. This excludes the incident in which 13 persons were shot dead by the police in Thoothukudi in 2018 during the Sterlite protests.

These custodial deaths raise serious questions about the unscientific nature of investigation in the state and the lack of accountability of police officers.

TNM examined the First Information Reports (FIR) of seven of the 27 reported cases for this story. We also spoke to families of seven victims, namely: Sathavayanan of Thanjavur, Thangamani of Tiruvannamalai, Appu alias Rajasekar of Chennai, Akash of Chennai, Karthi of Madurai, Baskar of Cuddalore, Manikandan of Ramanathapuram.

Arrested for petty crimes

Many of those who died in custody were arrested for petty crimes, and not for any large-scale financial crimes or high profile cases. Twelve of the men were in custody for alleged theft, or robbery. There were two instances of alleged bike snatching, one attempted murder case, and one brawl.

Police used violence as a tactic in investigation to elicit confession leading to grievous injuries. Also the victim's families were not financially sound enough to give proper treatment to them.

Take the case of Akash, who died in custody at Otteri on September 29, 2022. His mother Lakshmi told TNM that he was arrested in connection with a broken car window. She recounted, “He was the eldest of my two children. He was picked up by the police 10 days before his death. He never returned. My husband was so traumatised by Akash’s death that he passed away on October 15, just weeks later.”

Gandhimathi, wife of Baskar who died at Cuddalore in August 2024 shared a similar story. “We were daily wage workers. Baskar was arrested for allegedly selling tobacco and sent to Cuddalore jail. He told me he feared for his life. One day, the local town president received a call from the police informing them that my husband was in Cuddalore Government Hospital. By the time we arrived, he was dead.”

Signs of torture

Manikandan, a third-year BA English student, was picked up by the Ramanathapuram police for merely failing to stop his bike during a routine traffic check. His relative Radhika said, “He had gone out to buy a birthday cake.”

Radhika recollected how Manikandan had vomited blood when he reached home later that day. “When he vomited blood at home, the police said it was due to a snake bite or that he could have consumed poison,” she said. At the time, the police said he had died by consuming poison, but his family raised questions after the post-mortem report showed multiple injuries.

In the 2022 custodial death of Vignesh in Chennai, there were allegations that the police had instructed that the body be cremated and not buried, presumably so that it may not be exhumed for medical examination later on. The family, who were not allowed to see his body, also accused the police of trying to cover up his custodial murder by paying them hush money. While the police stated he had died of ‘seizure’, the post-mortem report detailed extreme horrors, including at least 44 injuries.

Epileptic seizure is one of the top cited causes for death by the police in a total of six cases — Thangapandi (33), Gokul Sri (17), Karthi (30), Thadiveeran(38), Vignesh (25), Ajith Kumar (29). Other reasons cited include chest pain, general uneasiness, vomiting, and miscellaneous ailments. But post-mortem reports often told a different story.

Cause of death

The family of Appu, alias Rajsekhar, learned about his death through a TV news report. He died in custody at Kodungaiyur in Chennai in June 2022. “His body was covered in injuries. His fingers were broken and he had injuries on his knees. We are certain he was tortured to death. They said he died of seizures, but we know the truth. Police officers from Sholavaram, Villivakkam, and Mylapore urged us to withdraw the case. They even offered us Rs 20–50 lakh to settle,” Appu’s brother Manikandan told TNM.

Thirty-three-year-old lorry driver Sathyavannan died in August 2021 in Thanjavur. His mother recounted how she heard of his death, “One day, police officers came to our house asking for him. We weren't informed about any arrest. Suddenly, they told us he was dead. The police claimed he died of typhoid and had been arrested in connection with a theft case. We never saw him after the arrest. His body had visible injuries, and blood marks on his nose and feet. We firmly believe my son was killed after a brutal assault. No action has been taken against the police officials involved.”

Minors have also not been spared from torture.

On December 29, 2022, Gokul Sree, a 17-year-old resident of West Kannadapalayam in Tambaram, was arrested for allegedly trying to steal batteries from railway premises by the Railway Police Force. Later, he was lodged at the Chengalpattu juvenile reform home.

The day after his detention, on December 31, Gokul fell seriously ill and died shortly after being rushed to Chengalpattu Government Hospital. The staff of the home alleged the death was due to food poisoning, but his mother noticed visible injuries on his body. The FIR filed by the police said that Gokul had a history of seizures and that he died after developing one around 4 am on December 31, 2022.

A post-mortem examination revealed 96 different injuries, including contusions, abrasions, and wounds possibly inflicted by blunt-edged weapons. The cause of death was confirmed as shock and hemorrhage from torture.

Following a magistrate inquiry, six personnel from the juvenile correctional facility in Chengalpattu, including the superintendent and wardens, were arrested under IPC Section 302 (murder). The case is now being investigated by the CB-CID.

“Though the investigation is progressing slowly, I believe justice is still possible. The truth is out there and the evidence clearly shows what was done to my son. We are holding on to hope,” Gokul’s mother Priya told TNM.

Dalit victims

Of the 27 cases, 9 were from Scheduled Castes while two persons including Marimuthu were from the Scheduled Tribes community.

Two of the victims were from the Most Backward Classes (MBC) and two including Ajith Kumar, were from the Backward Classes (BC). The list also includes one, Muslim and one minor. The caste of 12 victims could not be verified.

“Half of the custodial deaths are from Scheduled Caste and Scheduled Tribes. Isn't it a shame for the ‘social justice government’? Is this the way Dalits are to be treated?” asked Henri Tiphagne, executive director of People’s Watch.

This includes the case of Thangamani, a member of the Malai Kuravar tribe, picked up by the police in Tiruvannamalai in February 2022 for allegedly brewing illicit liquor. According to the police, he suddenly developed seizures while in custody and died the next day.

Baskar, a Dalit man arrested by the police in 2024 in Cuddalore, died after falling sick after being remanded, the police say. The FIR says, “He was found in his cell sweating and did not wake up in the morning. He was sent to the Government Hospital in an auto rickshaw in the morning but the doctor who examined him said that he had died en route.”

Talking to TNM, his wife Gandhimathi said that he was subjected to torture and that there were bruises all over his body and swelling on his face.

Action against cops

Lokniti – Centre for the Study Developing Societies (CSDS) report titled State of Policing 2025 put Tamil Nadu at second place after Gujarat where police endorsed custodial torture. The report says, 56% of police personnel in Tamil Nadu expressed ‘high support’ for the idea that violence is sometimes necessary and acceptable to gain information while 17% expressed ‘moderate support’.

According to NCRB data, only one police officer has been convicted for custodial violence in Tamil Nadu between 2011 and 2022. It was in 2013. In 23 cases, between 2016 and 2022, the **National Human Rights Commission (NHRC)** recommended monetary compensation totalling Rs 62.25 lakh to victims of torture or their kin.

In Tamil Nadu, even cases that have received significant public attention are yet to be closed. Final judgement is pending even in the Sathankulam custodial deaths of P Jayaraj and J Bennix in 2020.

“In most of the cases legal interventions were initiated but there is no fast track process in the lower courts or High Court regarding custodial deaths. Whenever we ask for CCTV footage, the state public prosecutor states that it was deleted within 15 days, which is illegal. Shouldn’t the court have immediately pulled up the police for that? The least that the High Court can do is ask the legal authorities to investigate and file a report and ensure that the District Level Oversight Committee (DLOC) and State Level Oversight Committee (SLOC) to oversee CCTVs in police stations are active,” Henri said.

Advocate Edgar Kaiser of People’s Watch echoed a similar view: “The police machinery definitely needs to be revamped. If public trust in police is not restored under Stalin’s leadership, it would simply be a betrayal of the principles espoused by Periyar and Anna.”

The Indian Express

BJP takes objection to ‘halal lifestyle township’ in Karjat

"We are already dealing with one Pakistan which was an outcome of painful partition. Now we cannot allow seeds of partition to be sown again in the name of religion," Upadhye said.

https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/bjp-takes-objection-to-halal-lifestyle-township-in-karjat-10242096/lite/

By: Express News Service | September 10, 2025 06:41 PM IST

1 min read

BJP state spokesperson Keshav Upadhye on Wednesday objected to the growing trend of pushing residential projects through ‘halal lifestyle township’ by some developers in Mumbai and its suburbs.

Taking serious objection to promoting housing projects on religious lines, Upadhye said, “Marketing residential properties using religious context is unacceptable. When you mention ‘halal lifestyle township’, it clearly depicts the discriminatory mindset. Such divisive method does not augur well for any society. It promotes division and hatred against each other. It should not be allowed.”

The BJP leader’s response was to a proposed ‘halal lifestyle township’ near Karjat, nearly 100 km from Mumbai.

“We are already dealing with one Pakistan which was an outcome of painful partition. Now we cannot allow seeds of partition to be sown again in the name of religion,” Upadhye said.

Meanwhile, National Human Rights Commission has reportedly taken cognisance of a complaint over the Karjat project and sought a report from the state government. It has also sought a clarification from housing regulator MahaRERA about the legal basis for approving it.

Deccan Herald

BJP objects to use of religion as pitch for housing projects, calls it threat to national unity

The National Human Rights Commission has reportedly taken cognisance of a complaint over the Karjat project and sought a report from the state government, besides also seeking clarification from housing regulator MahaRERA about the legal basis for approving it.

https://www.deccanherald.com/india/maharashtra/bjp-objects-to-use-of-religion-as-pitch-for-housing-projects-calls-it-threat-to-national-unity-3720940

PTI Last Updated : 10 September 2025, 14:39 IST

Mumbai: Maharashtra BJP spokesperson Keshav Upadhye has criticised the use of religion to promote residential projects, calling it a divisive tactic that undermines constitutional values and national unity.

“Our main objection is to such a pitch for the sale of residential properties. It is unacceptable,” Upadhye said recently, referring to a proposed “halal lifestyle township” near Karjat, about 100 km from Mumbai.

The National Human Rights Commission has reportedly taken cognisance of a complaint over the Karjat project and sought a report from the state government, besides also seeking clarification from housing regulator MahaRERA about the legal basis for approving it.

Upadhye said that such religion-branded projects attempt to sow seeds of partition. “Those seeking to erect walls of religious division in society by creating such ‘halal lifestyle townships’ around Mumbai must face action,” he said.

“After the 1857 revolt, Sir Syed Ahmed Khan had demanded separate spaces for Muslims, a move viewed as the first demand for partition. Today’s halal township in Karjat must be seen as a danger bell to the nation’s unity,” he said.

The BJP leader said the project uses promotional wordings like “everything will be halal in the society”. Such descriptions amount to “a direct assault on constitutional values and deliberately foster division and discrimination.” “If such projects are allowed today, tomorrow we will see separate colonies for every religion in every district and village. That would pose a grave threat to India’s social harmony, unity and security,” said Upadhye.

He urged the government to launch a probe and asserted that no conspiracy to divide society in the name of religion will be tolerated.

“Plotting division under the guise of development is land jihad. Let those behind such plans understand – there is no place for any form of jihad or fatwa in Maharashtra,” Upadhye said.

National Herald

Halal homes? Outrage! But sorry, regular flats not for you either

Maharashtra BJP says 'halal lifestyle' housing project in Karjat 'threatens social unity and constitutional values'

https://www.nationalheraldindia.com/amp/story/national/maharashtra-bjp-raises-alarm-over-halal-lifestyle-township-near-karjat

By Aditya Anand | Published: 10 Sep 2025, 5:40 PM IST

In yet another spectacular display of selective outrage, Maharashtra's ruling BJP has discovered its latest existential threat: a proposed 'halal lifestyle township' near Karjat, 100 km from Mumbai. Apparently, Muslims trying to live in houses where they won't be turned away at the gate is now a "direct assault on constitutional values".

Party spokesperson Keshav Upadhye fumed that using religion to promote real estate was unacceptable and "divisive". That would be almost touching in its idealism — if Muslims weren't already routinely shown the door when they apply for flats in Hindu housing societies. One might call this hypocrisy, but in the world of Indian politics it passes for consistency.

The National Human Rights Commission has taken notice of the Karjat project and MahaRERA is busy checking paperwork, because nothing alarms the state quite like Muslims daring to organise their housing in a country where the phrase "no Muslims allowed" has appeared more than once in rental ads.

Upadhye thundered that projects like Karjat build "walls of religious separation". One wonders where he was when Mumbai brokers openly admitted they wouldn't show properties in Hindu colonies to Muslim clients, or when a Muslim couple in Noida was turned away from a housing society because "residents were uncomfortable", or when late-night protests broke out in Moradabad's posh TDI City housing society after a house in the Hindu-majority colony was sold to a Muslim doctor.

Apparently, discrimination is acceptable when it's unspoken and practised by private societies — but intolerable if Muslims seek to bypass it by creating their own safe spaces.

To really drive the point home, Upadhye reached for the ghosts of 1857, invoking Sir Syed Ahmed Khan as though a township in Karjat were the second coming of Partition. The historical melodrama was perhaps meant to mask the awkward reality that Muslims today often find their housing options shrinking to ghettos — not by choice, but by exclusion.

"Everything will be halal in the society," promised the township's marketing. To Upadhye, this was practically jihad with bricks and mortar. If allowed, he warned, "tomorrow we could see separate colonies for every religion". The irony, of course, is that tomorrow is already here: many Hindu co-operatives quietly (sometimes not so quietly) maintain religious exclusivity, while Muslim buyers are steered away.

The spokesperson went so far as to call the project “land jihad”, a phrase designed to conjure conspiracy while ignoring plain facts. The plain fact being that Muslims in cities like Mumbai, Ahmedabad, and Delhi are routinely denied homes in 'mixed' societies — remember the Gujarat housing boards that effectively corralled Muslims into Ahmedabad's Juhapura, or the brokers in Bengaluru caught on camera refusing to rent to them?

So, to summarise the BJP’s position: Muslims cannot buy into Hindu-majority neighbourhoods, because that’s unsettling. They also cannot build their own neighbourhoods, because that’s divisive. They must simply exist, housing optional, preferably invisible.

One wonders if the next innovation will be a government directive telling Muslims exactly which pavements are designated for sleeping on. After all, unity demands sacrifice.

IBC24 News

भाजपा ने आवासीय परियोजनाओं के लिए धर्म के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई

https://www.ibc24.in/maharashtra/bjp-objects-to-use-of-religion-for-housing-projects-3245552.html

Bhasha | Modified Date: September 10, 2025 / 04:20 pm IST

Published Date: September 10, 2025 4:20 pm IST

मुंबई, 10 सितंबर (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महाराष्ट्र इकाई के प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने धर्म के आधार पर आवासीय परियोजनाओं के प्रचार की आलोचना करते हुए इसे ‘‘संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा’’ करार दिया।

उन्होंने हाल में कर्जत (मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर) में प्रस्तावित ‘‘हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप’’ का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘हमारी आपत्ति आवासीय संपत्तियों की बिक्री के लिए इस तरह के प्रस्ताव पर है। यह अस्वीकार्य है।।’’

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस परियोजना पर दायर शिकायत का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है और साथ ही

महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महरेरा) से इसकी मंजूरी के कानूनी आधार पर स्पष्टीकरण तलब किया है।

उपाध्याय ने कहा कि इस तरह की धर्म-आधारित परियोजनाएं विभाजन का बीज बोने का काम करती हैं।

उन्होंने कहा, ‘मुंबई के आसपास इस तरह की ‘हलाल टाउनशिप’ बनाकर समाज में धार्मिक विभाजन की दीवारें खड़ी करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।’

उन्होंने कहा, ‘वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए अलग जगह की मांग की थी, जिसे विभाजन की पहली मांग माना गया। कर्जत में प्रस्तावित ‘हलाल टाउनशिप’ को देश की एकता के लिए खतरे की घंटी के रूप में देखा जाना चाहिए।’

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि परियोजना के प्रचार में ‘‘सोसाइटी में सबकुछ हलाल होगा’’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ‘‘संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला और समाज को बांटने की कोशिश’’ है।

उपाध्याय ने कहा, ‘अगर आज ऐसी परियोजनाओं को अनुमति दी गई, तो कल हम हर जिले और गांव में हर धर्म के लिए अलग-अलग बस्तियां देखेंगे। इससे भारत के सामाजिक सद्भाव, एकता और सुरक्षा को गंभीर खतरा होगा।’

उन्होंने सरकार से जांच शुरू करने का आग्रह किया और कहा कि धर्म के नाम पर समाज को बांटने की किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उपाध्याय ने कहा, 'विकास की आड़ में जमीन के बंटवारे की साजिश करना जमीन जिहाद है। ऐसी योजनाओं के पीछे जो लोग हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि महाराष्ट्र में किसी भी तरह के जिहाद या फतवे के लिए कोई जगह नहीं है।'

भाषा राखी अविनाश

अविनाश

G Exress News

विशेष निरीक्षक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली का भरतपुर यात्रा कार्यक्रम प्रस्तावित

https://gexpressnews.com/53271

एक्सप्रेस न्यूज़ डेस्क | Sep 10, 2025 - 19:30

भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) विशेष निरीक्षक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली बाल कृष्ण गोयल का 11 से 12 सितम्बर तक भरतपुर यात्रा कार्यक्रम प्रस्तावित है।

जिला कलक्टर कमर चौधरी ने बताया कि बालकृष्ण गोयल विशेष निरीक्षक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली का 11 से 12 सितम्बर तक भरतपुर यात्रा कार्यक्रम प्रस्तावित है। बालकृष्ण गोयल के भरतपुर प्रवास के दौरान 12 सितम्बर को प्रातः 10 से 11 बजे तक भरतपुर विकास प्राधिकरण के मीटिंग हॉल में बैठक लिया जाना प्रस्तावित है।

Navbharat Times

रामस्वरूप में ABVP लाठीचार्ज पर NHRC सख्त, यूपी के मुख्य सचिव और DGP से कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/lucknow/shri-ramswaroop-memorial-university-llb-abvp-case-nhrc-summon-report-from-up-chief-secretary-and-dgp-news/articleshow/123799247.cms

Compiled by: ऐश्वर्य कुमार राय | नवभारतटाइम्स.कॉम•10 Sept 2025, 9:30 am

बाराबंकी श्रीरामस्वरूप यूनिवर्सिटी प्रकरण में एनएचआरसी सख्त हो गया है। आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर दी है। आयोग ने जांच कर कर्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए 15 दिन का समय दिया है। इस मामले में लाठीचार्ज के बाद मामला गरमा गया था।

रामस्वरूप यूनिवर्सिटी बाराबंकी केस

अभय सिंह राठौड़, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी स्थित श्रीरामस्वरूप मेमोरियल विवि में कथित फर्जी एलएलबी दाखिले और छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने इसे प्रथम दृष्टया गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी से लगाए गए अरोपों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। आयोग ने जिम्मेदार अधिकारियों को इसके लिए 15 दिन का समय दिया है।

शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में एनएचआरसी को बताया कि विश्वविद्यालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिबंधों को दरकिनार कर अवैध दाखिले किए। साथ ही इसको लेकर जब छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जिसमें कई छात्र घायल हो गए है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि इस कार्रवाई से छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।शिकायतकर्ता ने आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। साथ ही शिकायतकर्ता ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच, जिम्मेदार विवि और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही घायल छात्रों के इलाज के लिए मुआवजा देने का अनुरोध भी किया है। वहीं आयोग ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़िता के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन प्रतीत हो रहे हैं।

वहीं मामले की सुनवाई आयोग की सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। पीठ ने इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के अंतर्गत संज्ञान में लिया और यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी यूपी को नोटिस जारी कर जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट की एक प्रति आयोग को ईमेल के माध्यम से भी भेजी जाए। फिलहाल इस मामले में आयोग को राज्य सरकार और पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट का इंतजार है।

Mridubhashi

लखनऊ: ABVP छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर NHRC सख्त, मुख्य सचिव-DGP से जवाब मांगा

https://mradubhashi.com/news.php?id=lucknow-nhrc-strict-on-police-action-on-abvp-students-seeks-answer-from-chief-secretary-dgp-575620

Updated on 10 Sep, 2025 11:40 AM IST BY MRADUBHASHI.COM

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी स्थित श्रीरामस्वरूप मेमोरियल विवि में कथित फर्जी एलएलबी दाखिले और छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने इसे प्रथम दृष्टया गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी से लगाए गए अरोपों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। आयोग ने जिम्मेदार अधिकारियों को इसके लिए 15 दिन का समय दिया है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में एनएचआरसी को बताया कि विश्वविद्यालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिबंधों को दरकिनार कर अवैध दाखिले किए। साथ ही इसको लेकर जब छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जिसमें कई छात्र घायल हो गए है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि इस कार्रवाई से छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

शिकायतकर्ता ने आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। साथ ही शिकायतकर्ता ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच, जिम्मेदार विवि और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही घायल छात्रों के इलाज के लिए मुआवजा देने का अनुरोध भी किया है। वहीं आयोग ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़िता के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन प्रतीत हो रहे हैं। वहीं मामले की सुनवाई आयोग की सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। पीठ ने इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के अंतर्गत संज्ञान में लिया और यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी यूपी को नोटिस जारी कर जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट की एक प्रति आयोग को ईमेल के माध्यम से भी भेजी जाए। फिलहाल इस मामले में आयोग को राज्य सरकार और पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट का इंतजार है।

Lagatar.in

पलामू : नवजात को 50 हजार में बेचने के मामले में NHRC ने लिया संज्ञान

https://lagatar.in/palamu-nhrc-takes-cognizance-of-the-case-of-selling-a-newborn-for-rs-50-thousand

By Lagatar News | Sep 10, 2025 03:51 PM

चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन ने की थी शिकायत

Palamu : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पलामू जिले में पैसे की कमी के कारण नवजात बच्चे को 50 हजार रुपये में बेचे जाने के मामले में संज्ञान लिया है. इसको लेकर चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ कुमार ने शिकायत की थी.

सचिव बैद्यनाथ कुमार ने अपनी शिकायत में लिखा था कि नीलांबर-पीतांबरपुर प्रखंड (लेस्लीगंज) के लोटवा गांव की पिंकी ने इलाज के लिए अपने मासूम बच्चे को 50 हजार रूपये में बेच दिया. पिंकी देवी ने बताया कि उसके स्तन में गिलटी है. इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरन बच्चे को बेचना पड़ा.

फाउंडेशन ने अपनी शिकायत में लिखा कि पिंकी देवी के परिवार में किसी भी सदस्य के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड नहीं है. इस वजह से वह सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं. लेस्लीगंज बीडीओ सुकेशनी केरकेट्टा ने उन्हें चावल उपलब्ध कराया, लेकिन मात्र 20 किलो.

सभी मंदिर के शेड में रहने को मजबूर हैं. जिला प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसलिए वह अपने नवजात बच्चे को बेचने पर मजबूर हुई. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत यह अपराध है. हालांकि यह मामला मानवधिकार हनन का प्रतीत होता है.

आजादी के इतने वर्षों बाद भी एक अनुसूचित जाति के परिवार को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखना जिला प्रशासन की घोर लापरवाही को दर्शाता है.

Amar Ujala

Damoh: मुकेश नायक बोले- मिशन अस्पताल में 30 मौतों और गंगा जमुना स्कूल बंद होने की जिम्मेदारी कौन लेगा?

https://www.amarujala.com/video/madhya-pradesh/damoh/former-minister-asked-who-is-responsible-for-30-deaths-due-to-closure-of-mission-hospital-damoh-news-c-1-1-noi1223-3388118-2025-09-10

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: दमोह ब्यूरो Updated Wed, 10 Sep 2025 09:02 AM IST

कांग्रेस के पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने दमोह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिशन अस्पताल और गंगा जमुना स्कूल को जानबूझकर बंद करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं के बंद होने से आम जनता को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर नुकसान हुआ है। मुकेश नायक ने कहा कि मिशन अस्पताल में इलाज के अभाव में करीब 30 लोगों की मौत हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में लापरवाही बरती गई और फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एनजोन केम की वजह से मरीजों की जान गई। नायक ने कहा कि कई मरीजों को अब जबलपुर जाकर डायलिसिस करवाना पड़ रहा है।

पूर्व मंत्री ने गंगा जमुना स्कूल को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि करीब डेढ़ साल पहले इस स्कूल पर धर्म परिवर्तन, छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने और धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने के आरोप लगे थे। नायक ने कहा कि आरटीआई में जानकारी मिली कि पिछले 20 वर्षों में दमोह में कोई धर्मांतरण का मामला नहीं आया इसलिए स्कूल को बंद करना एक सोची-समझी साजिश है।

मानव अधिकार आयोग पर भी साधा निशाना

मुकेश नायक ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग की भूमिका में अनियमितता रही और जांच कराना जरूरी है। नायक ने कहा कि जनता के हित में इन दोनों संस्थाओं को दोबारा खोलने की कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व मंत्री ने जोर देकर कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह कदम सीधे गरीब और आम जनता को प्रभावित कर रहा है।